

दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के विपरीत है।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी धार क्षेत्रों को बाड़मेर एवं जालौर में पानी पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊंचाई कडारगा बांध बनाने की सहमति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी हिस्सा डब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था।

14.59 hrs.

[SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*]

राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों की बैठक इस विषय में दिनांक 6-4-83 को केन्द्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। परन्तु अभी तक कोई माकूल हल नहीं निकला।

यह प्रश्न राजस्थान प्रान्त के विशेषतः थार रेगिस्तान के क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है।

अतः केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि इस अविलम्बनीय प्रश्न को या तो खुद जल्दी से जल्दी हल करे या तुरन्त से तुरन्त जलस्रोत कौमिल नेशनल वाटर रिसोसिज काउंसिल में रखा जावे और राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालौर जिलों में माही नदी का पानी पहुंचा कर उक्त क्षेत्र को सिंचित कर हरा-भरा किया जा सके।

15.00 hrs.

(iv) Demand for railway facilities in Bidar district of Karnataka.

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी (बीदर) : बीदर रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म नं० 1 से 2 पर जाने आने के लिए ओवर ब्रिज प्लेट फार्म नं० 2 पर छत तुरंत करने की आवश्यकता है। साथ ही इस रेलवे बड़ी लाइन पर सिकंदराबाद-परली गाड़ी चलती है, जो कि बहुत ही धीमी गति से चलती है। बीदर से हैदराबाद सिर्फ 130/150 किलोमीटर के भीतर है और पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय लगता है। बीदर में हवाई दल का ट्रेनिंग

स्कूल है। साथ ही व्यापार और धार्मिक पवित्र स्थल के कारण यात्रियों का आना जाना ज्यादा है। यात्रियों की जरूरत को ख्याल में रखते हुए एक जल्दी रेल सिकंदराबाद से बीदर जारी करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा करने से हैदराबाद, बंगलोर, दिल्ली, मद्रास तथा हिन्दुस्तान के हर कोने में आने जाने वालों को सुविधा होगी।

(v) Resettlement of Ex-servicemen in Vajay Nagar, Arunachal Pradesh.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna) : Following the discovery of the Lissus and Yobins of Chinese origin living in the sensitive area of Vijaynagar in Tirap district of Arunachal Pradesh, especially after the conflict with China in 1962, government was keen to neutralise the deep penetration of these foreign tribals by resettling the families of ex-servicemen in that area. Strong inducements like allotment of upto 50 acres of land per family for cultivation and housing, besides other facilities including free air lift upto Mohanbari were accordingly offered to ex-servicemen and about 200 families of former Assam Rifles personnel were settled in the area.

These former armed forces personnel are however now very unhappy for they feel neglected and let down because of non-fulfilment of the assurances given to them both by the Central and local governments. While the foreign tribals are no longer confined to Gandhigram and are flourishing and spreading out encroaching upon the lands of the ex-servicemen the land for the ex-army personnels is yet to be demarcated and documented. While the ex-servicemen have no electricity and tap water facilities so far the foreigners are enjoying these facilities. The free air passage facility also has since been withdrawn.

Vijaynagar is a highly sensitive and strategic area with Burma on three sides.

I would therefore urge upon the government to accord top priority to the fulfilment of the promises given to them, namely